अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

COVID-19 आजीविका सर्वेक्षण

मध्य प्रदेश (ग्रामीण)

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोज़गार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने प्रदान और सृजनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश(ग्रामीण) के ५२५ उत्तरदाताओं का एक विस्तृत फ़ोन सर्वेक्षण किया।

उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि के द्वारा किया गया था जिससे उनके कार्य और स्थान में विविधता सुनिश्चित की जा सके।यह प्रतिदर्श (सैंपल) राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

यहाँ प्रस्तुत डेटा १४ अप्रिल, २०२० और २३ मई, २०२० के बीच एकत्रित किया गया था। यह सर्वेक्षण परिणाम राज्य-स्तरीय संक्षिप्त जानकारी की एक श्रृंखला का हिस्सा है। विस्तृत जानकारी *cse.azimpremjiuniversity.edu.in* पर उपलब्ध है।

मुख्य निष्कर्ष

४८%
श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है।

२५%
परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

३६%
वंचित परिवारों को नकद अंतरण नहीं मिला।

१० मैं से ७
परिवारों ने बताया कि पहले की तुलना में वो अब कम खाना खा रहे हैं।

६६%
वंचित परिवारों को राशन मिला।

राहत उपायों की घोषणा

एसएमएस के माध्यम से सर्वेक्षण उत्तरदाताओं को राहत उपाय की जानकारी भेजी गई थी।

केंद्रीय स्तर

* हर परिवार को प्रति व्यक्ति ५ किलो अनाज (चावल/गेहूँ) और प्रति परिवार १ किलो दाल अप्रेल से जून २०२० तक हर महीने मुफ्त दिया जाएगा । यह नियमित राशन के अतिरिक्त है जो उन्हें मिलता रहेगा।
* अप्रेल से जून २०२० तक, हर महीने, महिला जन धन खाता धारकों के खाते में रु 500 की राशि जमा की जाएगी ।
* पीएम-किसन योजना की प्रथम किश्त (रु २०००) अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में दी जाएगी ।

राज्य स्तर

* जरूरतमंद परिवार, जो एनएफएसए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन राज्य समागम सुरक्षा पोर्टल के साथ पंजीकृत हैं उन्हें प्रति व्यक्ति ४ किलोग्राम गेहूं और १ किलो चावल मुफ्त में दिया जायेगा।
* पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को १००० रुपये का भुगतान मिलेगा।
* मध्याह्न भोजन के लाभार्थियों को मध्याह्न भोजन के बराबर की राशि का नकद हस्तांतरण मिलेगा ।
* राज्य पेंशनरों को दो महीने की पेंशन का अग्रिम भुगतान मिलेग।
* बैगा, सहरिया और भारिया परिवारों को अप्रैल और मई के मासिक हस्तांतरण का अग्रिम भुगतान एक बार में मिलेगा।

Source : covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures

अनुशंसाएँ

* पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए।
* दो महीने के लिए कम से कम रु 7000 का नकद हस्तांतरण (ट्रांसफर) दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए बड़े हस्तांतरण की आवश्यकता है।
* नकद हस्तांतरण की पहुंच का विस्तार करने के लिए मनरेगा, पीएम उज्जवला, पीडीएस और स्थानीय पंजीकरण से जानकारी का उपयोग करें।
* शहरी गरीबों के लिए कार्यक्रमों पर जोर देने की जरूरत है।
* मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की जरूरत है।

आजीविका पर प्रभाव

यह भाग तालाबंदी के चलते काम और कमाई पर पड़े असर को समझने की कोशिश करता है। तालाबंदी लागू होने के बाद के रोज़गार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है।

चित्र १: जिन श्रमिकों ने रोजगार खोया है (गतिविधि की स्थिति के अनुसार) (%)

n = ५००

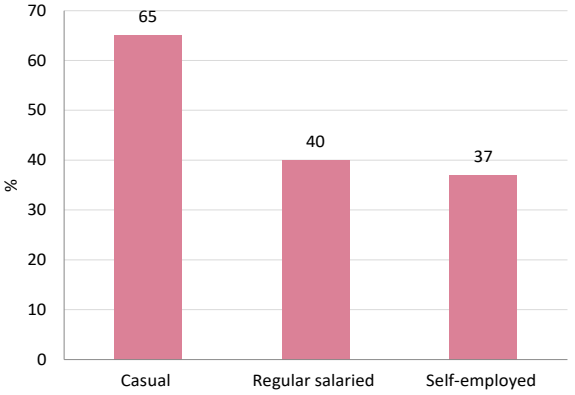

४८% ने बताया कि उन्होंने तालाबंदी के दौरान अपना रोज़गार खोया।

६५% दिहाड़ी श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया, वह तालाबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ।

१० में से ७ किसानों ने बताया कि वह अपनी उपज को पूरी कीमतों पर बेचने में असमर्थ हुए।

४४% वेतनभोगी मज़दूरों ने बताया कि उन्हें उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया या उन्हें लॉकडाउन के दौरान कम वेतन मिला ।

"सरकार जो कुछ भी कर रही है, वह गरीब और मजदूर वर्ग तक नहीं पहुँच रहा है।"
(पुरुष, २६, दिहाड़ी मज़दूर)

चित्र २: श्रमिक जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है (लिंग के अनुसार) (%)

n = ५००

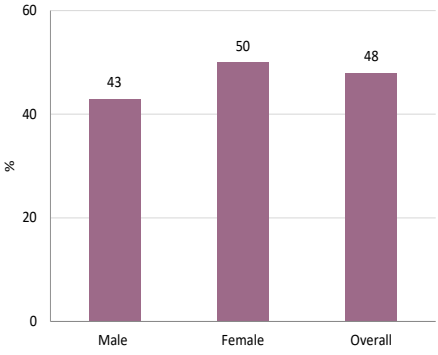

घरों पर प्रभाव

यह भाग यह देखता है परिवारों पर, खासकर उनके भोजन के सेवन अथवा कर्ज़े और बचत की स्तथिि पर, तालाबंदी के कारण क्या प्रभाव पड़ा।

चित्र ३: वंचित परिवारों के भोजन सेवन और बचत पर प्रभाव (%)

n = ४३२

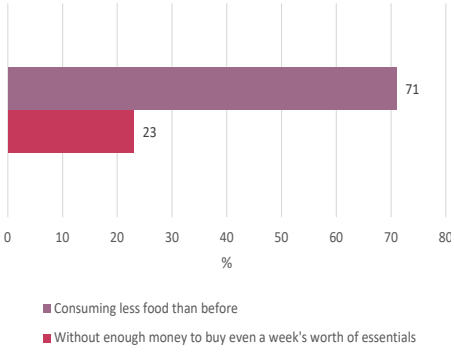

१० में से ७ परविारों ने बताय कि तालाबंदी के दौरान उन्होंने पहले कि तुलना में कम भोजन का सेवन कयिा।

एक-चौथाई परविारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

सामान्य (१९ %) और ओबीसी (१७ %) परविारों की तुलना में, एससी / एसटी परविारों (२५%) परविारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

एक-चौथाई परविारों को इस तालाबंदी के परणिामस्वरूप ऋण (कर्ज़ा)लेना पड़ा।

आधे से अधकि परविारों (५२%) ने कहा कि वह अगले महीने का करिाया नहीं दे सकते।

चित्र ४: वह परिवार जो कम भोजन का सेवन कर रहे हैं (परिवार की आय के मुख्य स्रोत के अनुसार) (%)

n = ५०३

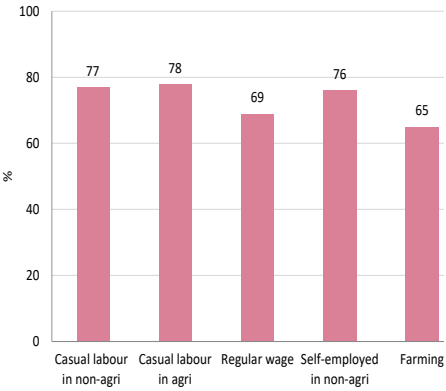

राहत योजनाओं की पहुँच

यह भाग सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों की पहुंच और प्रभाव का अध्ययन करता है। हम राशन की उपलब्धता, लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण और कमजोर परिवारों को मिलने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

चित्र ५: वंचित परिवार जिन्हे तालाबंदी के दौरान जन धन ट्रांसफर मिला (%)

n = ५०३

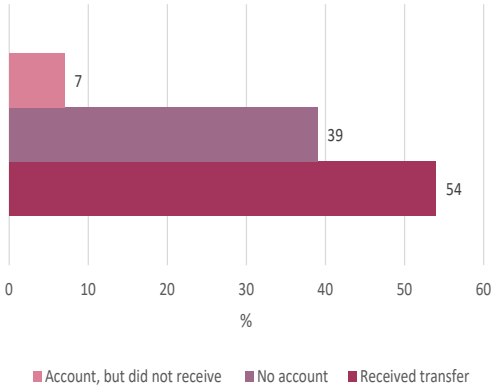

दो-तिहाई वंचित परिवारों को राशन मिला।

३९% वंचित परिवारों के पास जन धन खाता नहीं था, परन्तु जिन के पास खता था उनमे से ८९% को नकद हस्तांतरण प्राप्त हुआ।

३६% कमजोर परिवारों को कोई नकद हस्तांतरण नहीं मिला।

चित्र ६: वंचित परिवार जिनको राशन मिला (%)

n = ३६६

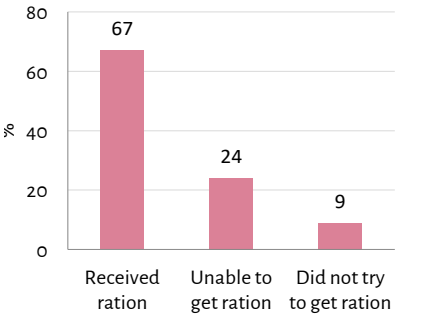

केवल एक-चौथाई किसानों को ही पीएम-किसन हस्तांतरण मिला।

३८% पेंशनरों को अपना पेंशन मिला।

सर्वेक्षण कवरेज

३७% उत्तरदाता पुरुष थे और ६३% महिलाएं थीं।

८६% उत्तरदाता हिन्द थे और बाकी १२% अन्य थे।

५८% उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति व जाती समुदाय से थे।

चित्र ७: फरवरी के महीने में उत्तरदाताओं की गतिविधि की स्थिति (%)

n = ५२५

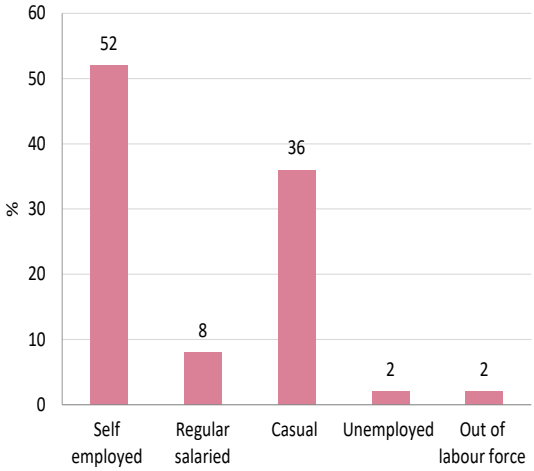

राज्य में हो रहे अन्य सर्वेक्षणों के परिणाम

* जन सहस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, निर्माण श्रमिकों में से केवल कुछ ही श्रमिकों को उनके नकद हस्तांतरण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश श्रमिक मध्य प्रदेश में निर्माण श्रमिक बोर्ड (BoCW) के साथ पंजीकृत नहीं है।

* इंडस एक्शन, आईआईटी-दिल्ली, फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज और रोड स्कॉलरज के द्वारा आयोजित शोध में अन्य राज्यों के साथ-साथ मध्य प्रदेश पर पड़े कोरोना के प्रभाव की भी व्याख्या की गयी है।

देश भर में किए गए विभिन्न कोविड़-19 सर्वेक्षणों और अध्ययनों के संकलन के लिए कृपया देखें: cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impactand-relief-measures/#other_surveys

सवाल के लिए: **Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University**
cse.azimpremjiuniversity.edu.in | cse@apu.edu.in